भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 727

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण

727. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

- (क) देश में 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत राज्यवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश राज्य में कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नयन के लिए अनुमोदित आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की वर्तमान भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या ब्यौरा क्या है;
- (ग) आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन को पूरा करने की क्या समय-सीमा तय की गई है तथा इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई है; और
- (घ) आंध्र प्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) की शुरुआत से लेकर आज तक इसके अंतर्गत शामिल की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) का उद्देश्य उचित और विविध पोषण सामग्री प्रदान करके बाल कुपोषण और मातृ कुपोषण की चुनौती का समाधान करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, तंदुरस्ती और प्रतिरक्षा को पोषित करने वाली पद्धतियां तैयार करने के लिए एक अभिसरण व्यवस्था तंत्र बनाना है। इस योजना मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंड, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरस्ती पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि आंगनवाड़ियों में पंजीकृत लाभार्थियों को पका हुआ गर्म भोजन और

घर ले जाने के लिए राशन प्रदान करके कुपोषण, अल्प वजन, ठिगनापन और एनीमिया को कम किया जा सके। 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग में पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत लाभार्थियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार विवरण (पोषण ट्रैकर डेटा, अक्टूबर 2024 के अनुसार) **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग) 15वें वित्त आयोग की समयावधि के दौरान बेहतर पोषण प्रदान करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए सरकारी भवनों में स्थित दो लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में सुदृढ़ और उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ी को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा जैसे इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, जल फिल्टरेशन प्रणाली/आरओ मशीन की स्थापना, पोषण वाटिका, ईसीसीई सामग्री आदि प्रदान किया जाना है। दिनांक 25.11.2024 तक, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 9958 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित देश भर में कुल 170337 आंगनवाड़ी केंद्रों को उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित 5837.38 लाख रुपये सहित देश भर के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100448.53 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(घ) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की सभी पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (किसी भी कारण से जीवन जोखिम, मृत्यु शामिल) के लिए बीमा लाभ प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में, आंध्र प्रदेश राज्य में पीएमजेबीवाई के तहत 40683 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और 37160 आंगनवाड़ी सहायिका शामिल की गई हैं।

अनुलग्नक

“सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण” के संबंध में श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव और श्री बी. के. पार्थसारथी द्वारा दिनांक 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 727 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थियों का आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार विवरण (पोषण ट्रैकर डेटा, अक्टूबर 2024 के अनुसार) इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थियों की संख्या (पोषण ट्रैकर डेटा, अक्टूबर 2024 के अनुसार)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9910
2	आंध्र प्रदेश	2480081
3	अरुणाचल प्रदेश	80706
4	असम	2729332
5	बिहार	9210632
6	छत्तीसगढ़	2140043
7	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	30836
8	दिल्ली	495591
9	गोवा	46347
10	गुजरात	2912829
11	हरियाणा	1644529
12	हिमाचल प्रदेश	455262
13	जम्मू और कश्मीर	706368
14	झारखंड	2765130
15	कर्नाटक	3572279
16	केरल	1783828
17	लद्दाख	16040
18	लक्षद्वीप	3374
19	मध्य प्रदेश	6269811
20	महाराष्ट्र	5776896

21	मणिपुर	262678
22	मेघालय	348553
23	मिजोरम	102849
24	नागालैंड	103416
25	ओडिशा	3267373
26	पुदुचेरी	27243
27	पंजाब	1351386
28	राजस्थान	3501757
29	सिक्किम	28788
30	तमिलनाडु	3361204
३१	तेलंगाना	1686621
32	त्रिपुरा	286648
33	चंडीगढ़	34056
34	उत्तर प्रदेश	18654105
35	उत्तराखंड	607040
36	पश्चिम बंगाल	7345735
	कुल	8,40,99,276